यह एक बड़ा फैसला

किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई सरकार जनभावनाओं का सम्मान करती हुई दिखे तो यह अच्छी बात ही मानी जानी चाहिए। दिक्कत सिर्फ यह है कि जनभावनाओं का सम्मान करने का यह ख्याल उत्तराखंड सरकार के मन में तब आया, जब चुनाव सिर पर आ चुके हैं।

नवीन पंडित।।

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आखिरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला कर लिया। खुद मुख्यमंत्री धामी ने ट्विटर पर विडियो के रूप में जारी एक बयान में बताया कि तीर्थ पुरोहितों, हक–हकूकधारियों और जनप्रतिनिधियों की ओर से मिल रहे फीडबैक और इस सिलसिले में गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर उनकी सरकार ने चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड एक्ट को वापस लेने का निर्णय किया है। उत्तराखंड के लिहाज से यह एक बड़ा फैसला है। इसका काफी समय से विरोध हो रहा था। खास तौर पर राज्य का पुरोहित समुदाय इस कानून और इसके जरिए स्थापित मंदिर प्रबंधन व्यवस्था का घोर विरोधी था। इन लोगों को समझाने–बुझाने की काफी कोशिश हुई, लेकिन वे कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। अब अगर सरकार अपने कदम पीछे खींचने को तैयार हुई है तो इसकी एक व्याख्या तो यही है कि सरकार जनभावनाओं के आगे झुकी है। किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई सरकार जनभावनाओं का सम्मान करती हुई दिखे तो यह अच्छी बात ही मानी जानी चाहिए। दिक्कत सिर्फ यह है कि जनभावनाओं का सम्मान करने का यह ख्याल उत्तराखंड सरकार के मन में तब आया, जब चुनाव सिर पर आ चुके हैं।

गौर करने की बात है कि न तो देवस्थानम बोर्ड गठित करने का यह फैसला हाल का है और न ही इसका विरोध नया है। दिसंबर 2019 में विधानसभा में इस बिल को पेश किए जाने पर सदन के अंदर ही नहीं, बाहर भी इसका कड़ा विरोध हुआ था। उसके बाद भी विरोध जारी रहा। लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग रही क्योंकि उसका कहना था कि अन्य राज्यों में की गई समानांतर व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बाद और राज्य के तीर्थस्थलों के समन्वित विकास के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। इससे न केवल तीर्थस्थलों पर दिखने वाली अव्यवस्था की स्थिति समाप्त होगी बल्कि यहां आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास का सुनियोजित और समन्वित प्रयास भी संभव होगा।

ऐसे में स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि जब इतना सोच–समझकर और राज्य के व्यापक हित में यह कदम उठाया गया था तो फिर अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि सरकार अपने इस सुविचारित कदम को वापस लेने को मजबूर हो गई? भले इस बीच राज्य ने तीन मुख्यमंत्री देख लिए हों, लेकिन सरकार तो बीजेपी की ही है। धामी सरकार ने अभी तक ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, जिससे पता चले कि सरकार के संज्ञान में इस बीच कोई नया तथ्य आया जिससे वस्तुस्थिति बदल गई। ऐसे में यही संभावना सबसे मजबूत दिखती है कि बीजेपी सरकार ने चुनावी नफा–नुकसान के मद्देनजर यह फैसला किया है। अगर ऐसा है तो यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। जनहित में उठाए गए कदमों की चुनावी हितों पर बलि देने की यह परंपरा किसी का भला नहीं करेगी।

सामाजिक अनुभूति

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

टेम्पोरल लोब मिर्गी के रोगियों में हाइपररिगॉइलिटी ने पहले सिद्धांतों को प्रेरित किया जो धार्मिकता को मस्तिष्क के अंग और लौकिक क्षेत्रों के साथ जोड़ते हैं, जबकि कार्यकारी पहलुओं और धर्म के अभियोगात्मक भूमिकाओं ने जांच को ललाट लोब की ओर मोड़ दिया। विश्लेषणात्मक अध्ययनों से पता चला है कि सामाजिक अनुभूति का धार्मिक विश्वास से गहरा संबंध है। इन जैसे परिणामों के लिए, आज विज्ञान यह जाँचने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि क्या धार्मिक विश्वास मस्तिष्क की सक्रियता के विशिष्ट पैटर्न से संबंधित है। हालांकि, वैज्ञानिक ज्ञान को धार्मिक ज्ञान से अलग करने की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति जिसमें अवरोधक और अनुयायी होते हैं। अवरोधकों में, डेलिसल बर्न है, जो अपने पाठ में है धार्मिक ज्ञान क्या है?

संपादकीय

असली खतरे पर पर्देदारी

वाजिब सवालों का जवाब तलाशने के बजाय सवाल करने वालों को ही कठघरे में खड़ा करने की प्रवृति, देश के सामने पैदा हो रहे बड़े खतरों में एक है। आखिर, मुसलमानों को मुख्यधारा में रखने के लिए उनकी कमियों पर पर्दा डालने की कीमत कब तक चुकानी होगी? क्या भारत उनका देश नहीं है? अगर भारत को वो अपना देश मानते हैं तो फिर उन्हें साथ रखने की चिंता किसी प्रबुद्ध वर्ग को क्यों करनी पड़ती है? मुसलमानों को खुश रखो वरना देश आंतरिक रूप से कमजोर हो जाएगा और बाहरी दुश्मन मजबूत हो जाएंगे– क्या यह ब्लैकमेलिंग नहीं है? मेरे इन तर्कों को प्रबुद्ध वर्ग यह कहकर खारिज कर सकता है कि ये सब मेरे कुत्सित मन की ऊपज है, हकीकत में कुछ ऐसा है ही नहीं। मुसलमान पहले से ही मुख्यधारा में हैं और उन्हें साथ रखने के लिए किसी तरह की ब्लैकमेलिंग की जगह ही नहीं है क्योंकि वो घोर राष्ट्रभक्त हैं। फिर कोई ये बताए कि किसी राजनीतिक दल को मुसलमानों का वोट पाने के लिए आतंकवाद पर नरम रहने की जरूरत क्यों पड़ती है? जनसंख्या नियंत्रण जैसे नितांत अनिवार्य विषय पर कानून को मुसलमानों पर अत्याचार का पिछला दरवाजा क्यों बताया जाता है? मुस्लिम समाज की रूढ़ियों से छेड़छाड़ नहीं किए जाने के वादे क्यों किए जाते हैं? इसलिए, यह कहना कि बहुसंख्यक मुसलमान उदार है, यह देश के सामने खड़े खतरे पर पर्दा डालने की सबसे बड़ी ड्रामेबाजी है। हां, जिन्हें लगता हो कि मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए राजनीतिक दलों के 'कट्टरपंथी वादे' का दावा ही निराधार है, उनसे मुझे कोई तर्क नहीं करना। वो ऐसे मुगालतों में जीने को आजाद हैं।

इससे राष्ट्र अपनी पूरी क्षमता से ना खुद की रक्षा कर सकेगा और न ही विकास के रास्ते पर उतनी रफ्तार हासिल कर सकेगा जितनी की उसमें ताकत है।

कुछ गंभीर सवाल

नवीन कुमार पाण्डेय।।

इसमें कोई संदेह नहीं कि धर्म संसद में जो कुछ हुआ, वह देश की एकता के लिए घातक है। मुसलमानों से मुकाबले के लिए शस्त्र उठाने का आह्वान हो या देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग, दोनों ही बातों में कम–से–कम मुसलमानों और वामपंथी विचारधारा के लोगों में खौफ पैदा करने की क्षमता तो है ही। स्वाभाविक है कि खौफ खाया व्यक्ति, समुदाय या वर्ग कभी मुख्यधारा में शामिल नहीं होगा। इससे राष्ट्र अपनी पूरी क्षमता से ना खुद की रक्षा कर सकेगा और न ही विकास के रास्ते पर उतनी रफ्तार हासिल कर सकेगा जितनी की उसमें ताकत है।

यानी, धर्म संसद में जो हुआ वो दुबारा नहीं हो, यह सुनिश्चित करना देशहित में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ धर्म संसद के आयोजकों और वहां विवादित बयान देने वाले साधु–संतों पर कठोर कार्रवाई करने मात्र से हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा और राष्ट्र के कमजोर होने या इसकी प्रगति में बाधा आने के खतरे खत्म हो जाएंगे? क्या ऐसे खतरे पैदा करने वाले और दूसरे कारक देश में मौजूद नहीं हैं? क्या इस्लाम को खतरा बताना महज एक एजेंडा है और क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना वाकई खतरनाक है? धर्म संसद के

तीसरे विवादित मुद्दे– महात्मा गांधी की आलोचना के सवाल पर सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर मां दुर्गा को वेश्या बताने और नारीवादी नजरिए से मर्यादा पुरुषोत्तम भवगान राम की आलोचना करने में बुराई नहीं है तो गांधी की आलोचना में भी कोई पाप नहीं, बशर्ते भाषा संयत हो। इसलिए कालीचरण महाराज से मेरा मतांतर भाषा की सीमा तक ही है।

वकील बिरादरी और नामचीन हस्तियों के एक वर्ग ने धर्म संसद के आलोक में देश–रक्षा की दुहाई दी। उसने क्रमशः सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति–प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है। यह वही वर्ग है जो 'भारत तेरे टुकड़े होंगे– इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह' के नारे का समर्थन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर करता है। सुप्रीम कोर्ट से सजायाफ्ता और राष्ट्रपति से दया याचिका खारिज आतंकवादी की फांसी की सजा रोकने की जीतोड़ कोशिश करता है। आपको लग सकता है कि चूंकि यह समाज का सबसे प्रबुद्ध तबका है, इसलिए भारत के टुकड़े करने का खुला ऐलान और यहां तक कि भारतीय संप्रुभता के सर्वोच्च संस्थान संसद पर हमला करने वाले का समर्थन देशहित में ही होगा।

संभव है आपकी सोच सही हो, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी अमेरिका चले गए होते तो देश के सामने कौन सा खतरा पैदा होता? क्या हर वक्त देशहित की चिंता में लीन इस प्रबुद्ध वर्ग से पूछा नहीं जाना चाहिए कि अब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल अमेरिका बल्कि वाइट हाउस भी गए, उन्होंने दुनिया की सर्वोच्च संस्था संयुक्त राष्ट्र को भी संबोधित किया तो भारत के सामने कौन सा खतरा पैदा हुआ और यहां का सामाजिक तानाबाना कैसे और कितना कमजोर हुआ?

सबसे दैदिप्यमान दिमाग वाले इस वर्ग के इरादे पर संदेह मैं भी नहीं करता। मुझे लगता है कि वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि करीब 22 करोड़ की जनसंख्या वाली देश की करीब 15 प्रतिशत मुसलमान आबादी को मुख्यधारा में जोड़कर रखा जा सके। इसीलिए, धर्म परिवर्तन, लव जिहाद जैसे मुद्दे को भी सिरे से खारिज करते हैं और उल्टे इसे मुसलमानों के खिलाफ अजेंडा बताते हैं।

अष्टयोग- 4916

3	4		5		1	6
	30	2	36		32	
5			1	7		4
6	38	4	34	1	26	5
4		5	7			1
	31		32	4	30	
2	3		4		6	7

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 4915 का हल

6	1	2	5	7	4	3
3	32	6	36	2	30	1
4	3	7	1	6	2	5
5	26	1	34	4	38	6
1	2	3	7	5	6	4
2	30	4	32	3	31	7
7	6	5	4	1	3	2

Jagrutidaur.com, Bangalore®

अपना ब्लॉग

क्यों 'खतरनाक' दिखने लगा हिंदू?

मोहन। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर हिंदू पाक साफ है, हर हिंदू उदार भावों से ओत–प्रोत है, किसी में कट्टरता का नामो–निशान नहीं, लेकिन इतिहास साक्षी है कि हिंदुओं ने अपने अंदर कभी किसी के खिलाफ घृणा के शाश्वत भाव का जड़ नहीं जमाने दिया। तात्कालिक और घटना विशेष मौकों पर नफरत का इजहार संभव है। अब भी अगर हिंदू या उसके धार्मिक नेता उग्र स्वभाव से ग्रस्त दिख रहे हैं तो वो उनकी मूल प्रवृत्ति नहीं बल्कि प्रतिक्रियात्मक प्रयोजन मात्र है। हां, अपने देश, अपनी संस्कृति का गौरव गान करने को लेकर वो मुखर जरूर हो रहे हैं जिससे न तो मुसलमानों और न भारत को ही किसी प्रकार का खतरा है। आखिर स्वदेशी संस्कारों के अपनाने से देश को ही खतरा कैसे हो सकता है? हां, जिन्हें देश से ज्यादा 'दूसरे' की चिंता है, उसे हिंदुओं के इस बदले मिजाज से जरूर खतरा महसूस होगा।

तो क्या मैंने यह कहा कि काली चरण महाराज की गिरफ्तारी गलत है? क्या यति नरसिम्हानंद गिरि और हाल ही में इस्लाम छोड़कर सनातनी हुए जितेंद्र नारायण सिंह